मोहम्मद अन्सारी

बनाम

भारत संघ और अन्य

(सिविल अपील सं. 10131/2016)

फरवरी 02, 2017

{दीपक मिश्रा और उदय उमेश ललित, न्यायाधिपतिगण]

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007- प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 - केंद्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण और अपील) नियम, 1965- भारत का संविधान – अनुच्छेद 226 - जीआरईएफ (जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स) कर्मियों से संबंधित मामला - सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी)/केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) का क्षेत्राधिकार/उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत - अपीलकर्ता, सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवाओं में जीआरईएफ के सदस्य, कैट के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए वित्तीय उन्नयन देने से इनकार करने का मुद्दा – न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के संबंध में सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति - न्यायाधिकरण ने माना कि इस मामले पर विचार करने का उसका अधिकार क्षेत्र था - हालाँकि, उच्च न्यायालय ने माना कि वित्तीय उन्नयन देने से इनकार करने की अपीलकर्ता की शिकायत के मामले में कैट के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं था और यहां तक कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास भी कोई क्षेत्राधिकार नहीं था - उचित उपाय उच्च न्यायालय में आवेदन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत था, या उचित वाद प्रस्तुत करने का - अपील पर, अभिनिर्धारित - जीआरईएफ के सदस्य सशस्त्र बलों से संबंधित हैं - सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास जीआरईएफ कर्मियों के लिए कोर्ट मार्शल के फैसले से उत्पन्न होने वाली अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र होगा - केवल इस सीमा तक एएफटी

का अधिकार क्षेत्र होगा - यदि सजा सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत आयोजित विभागीय कार्यवाही के माध्यम से जीआरईएफ कर्मियों पर लगाया जाता है, इसे पहले एएफटी के समक्ष उत्तेजित नहीं किया जा सकता है - एएफटी के पास 'सेवा मामलों-तथ्यों' से संबंधित जीआरईएफ कर्मियों की शिकायतों को सुनने और निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा – तथ्यो पर, उन्नयन के मुद्दे से निपटने के लिए कैट के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की कमी के कारण, उक्त निर्णय निरर्थक है -उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार कि उसके पास केवल अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद से निपटने का अधिकार क्षेत्र है, सहमति - चूंकि अपीलकर्ता द्वारा की गई शिकायत का वास्तव में किसी भी सक्षम मंच द्वारा समाधान नहीं किया गया है, अपीलकर्ता को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया :

1.1 सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्पष्ट रूप से बताता है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का गठन संघ के उक्त सशस्त्र बलों के सदस्यों को त्वरित और कम खर्चीला न्याय प्रदान करने के लिए तीनों सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) के सदस्यों को सेवा मामलों और कोर्ट-मार्शल के फैसलों से उत्पन्न अपीलों से संबंधित शिकायतों और विवादों के निपटारे के लिए किया गया है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जीआरईएफ (जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स) के सदस्य सशस्त्र बलों से संबंधित हैं। जीआरईएफ, एक विभागीय निर्माण एजेंसी है जो देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी आदि जैसी अन्य निर्माण एजेंसियों से अलग है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में परिचालन भूमिका में सेना का की सहायता करने वाला यह केंद्रीय सरकार द्वारा गठित और रखरखाव किया जाने वाला एक बल है। जीआरईएफ सीमा सड़क विकास बोर्ड

के तहत कार्य करता है, और इसकी इकाइयां सेना इकाइयों/उप इकाइयों जैसे टास्क फोर्स, सड़क निर्माण कंपनियों, सड़क रखरखाव प्लाटून आदि की तर्ज पर तैयार की जाती हैं। [पैरा 20, 24] [435-एफ-जी; 438-ई-जी]

1.2 अधिसूचना संख्या एसआरओ 329, अनुसूची ए में कुछ अपवाद दिए गए हैं। सेना अधिनियम 1950 के कुछ प्रावधान अर्थात धारा 10, 11, 13 से 17, 20, 22 से 24 [कमीशन, नियुक्ति और नामांकन से संबंधित 1950 अधिनियम के अध्याय III के अंतर्गत आते हैं], धारा 43, 44 [अध्याय VI के अंतर्गत आते हैं- अपराध अर्थात फर्जी नामांकन और नामांकन पर गलत उत्तर क्रमशः और धारा 71, 74 से 78 के खंड (डी), (ई), (एफ), (जी) और (के), खंड 9 (ई), (एफ) और (जे) धारा 80 और धारा 84 के खंड (ए), अध्याय VII के अंतर्गत आते हैं - दंड] को जीआरईएफ के नागरिक सदस्यों के लिए उनके आवेदन में छूट दी गई है, क्योंकि जीआरईएफ के नागरिक कर्मियों को 1950 अधिनियम के तहत कमीशन या नामांकित या नियुक्त नहीं किया गया है। और इसलिए, वे 1950 अधिनियम की धारा 3(xxi) में परिभाषित 'नियमित सेना' के सदस्य नहीं हैं। यही कारण है कि एसआरओ 329 की अनुसूची बी में निर्धारित 1950 अधिनियम के कुछ प्रावधानों को जीआरईएफ के सदस्यों के लिए उनके आवेदन में संशोधित किया गया है। यह इस तथ्य से मजबूत होता है कि जीआरईएफ कर्मियों को जीआरईएफ में विभिन्न नियुक्तियों/पदनामों में बल के नागरिक घटक के रूप में नियुक्त किया जाता है और 1950 अधिनियम के प्रयोजन के लिये एसआरओ 1001 दिनांक 20.5.1961 के तहत नियमित सेना में समकक्ष रैंक के साथ अधिसूचित किया गया। [पैरा 29] [441-सी-एफ]

1.3 वैधानिक ढांचे के मद्देनजर, यह प्रदर्शित होता है कि 1950 अधिनियम और सेना नियम, 1954 केवल अनुशासन के उद्देश्य से जीआरईएफ के नागरिक कर्मियों पर लागू किए गए हैं। कारण स्पष्ट हैं। जीआरईएफ केंद्र सरकार के अधिकार के तहत गठित और बनाए रखा गया एक बल है, इसकी इकाइयां भारतीय सेना की तर्ज पर स्थापित की गई

हैं, यह सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित सेना के साथ निकट समन्वय के तहत काम करती है, भारतीय सेना को अपनी संचालननात्मक भूमिका निभाना, आदि की सुविधा प्रदान करती है। इसलिए, यह उचित समझा गया है कि 1950 के अधिनियम को अनुशासन के हित में आवश्यक समझे जाने वाले केंद्र सरकार द्वारा गठित और बनाए गए बल पर लागू किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जीआरईएफ कर्मियों को विधायी योजना के तहत दोहरे अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन किया जाता है, और ऐसी व्यवस्था स्वीकार्य है जैसा कि आर विस्वान के मामले में माना गया है। जब अपराध ऐसा हो कि 1950 अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि जीआरईएफ तक बढ़ाया गया है, अनुशासन के उद्देश्य से लागू होते हैं, तो यह 1950 अधिनियम के तहत सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए खुला होगा, इसके प्रावधानों के तहत अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और यदि दोषी पाया गया, उचित दंड दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपराध किसी शत्रु, सक्रिय सेवा पर अपराध, विद्रोह, परित्याग, अवज्ञा आदि के संबंध में किया जाता है, तो अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए, मुकदमे के माध्यम से अपराधी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई कोर्ट मार्शल की अन्वीक्षा के द्वारा की जा सकती है। अन्य अनुशासनात्मक मामलों में, सक्षम प्राधिकारी केंद्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण और अपील) नियम, 1965- सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत आगे बढ़ने का निर्णय ले सकता है जिसमें अधिकतम स्वीकार्य सजा केवल 'सेवा से बर्खास्तगी' है। [पैरा 30] [441-जी-एच; 442-ए-डी]

1.4 2007 का अधिनियम 1950 अधिनियम, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन व्यक्तियों पर लागू किया गया है, इन अधिनियमों के अधीन सेवानिवृत्त कर्मियों, उनके आश्रितों, उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों सहित जहां तक यह उनकी सेवा से संबंधित है। इसकी धारा 4 और 5 के अनुसार गठित न्यायाधिकरण को सेवा मामलों में दोहरे क्षेत्राधिकार अर्थात् अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और अधिकार जैसा

कि धारा 14 में प्रदत्त है और अधिनियम की धारा 15 के तहत मार्शल कोर्ट के खिलाफ अपील के मामले में क्षेत्राधिकार। [पैरा 31] [442-ई]

1.5 जो कानूनी स्थिति उभर कर सामने आती है वह यह है कि एएफटी के पास (i) जीआरईएफ कर्मियों के लिए कोर्ट मार्शल के फैसलों से उत्पन्न अपीलों को सुनने का अधिकार क्षेत्र होगा। केवल इसी सीमा तक एएफटी का क्षेत्राधिकार होगा। साथ ही यदि सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत आयोजित विभागीय कार्यवाही के माध्यम से जीआरईएफ कर्मियों पर दंड लगाया जाता है तो उसे एएफटी के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है और (ii) एएफटी के पास शिकायतों को सुनने और निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। जीआरईएफ कर्मी अपनी सेवा के नियमों और शर्तों से संबंधित हैं या वैकल्पिक रूप से 'सेवा मामले' रखते हैं। [पैरा 33] [443-सी-डीआई

1.6 उच्च न्यायालय के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान, ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता के पक्ष में 5.11.2012 को अंतिम आदेश पारित किया था। ट्रिब्यूनल के पास अपीलकर्ता द्वारा उसके समक्ष उठाए गए अपग्रेडेशन या उसकी प्रकृति के मुद्दे से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। मुद्दे से निपटने के लिए अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की कमी के अभाव में, बिक्री निर्णय निरर्थक है। कानून में इसका कोई अस्तित्व नहीं है. यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित है कि पारित निर्णय निरर्थक है यदि यह किसी ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जिसके पास कोई अंतर्निहित क्षेत्राधिकार नहीं है। डिक्री को शून्यता कहे जाने को इस अर्थ में समझा जाना चाहिए कि यह डिक्री पारित करने वाली अदालत की शक्तियों का अधिकारातीत अधिकार है, न कि केवल शून्यकरणीय डिक्री। [पैरा 34] [443-ई-एफ]

हीरालाल मूलचंद दोषी बनाम बरोट रमन लाल रणछोड़दास [1993] 1 एससीआर 1113: (1993) 2 एससीसी 458 - पर भरोसा किया गया।

1.7 उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त इस विचार से सहमति है कि अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद से निपटने का अधिकार केवल उसके पास है। भारत संघ और उसके पदाधिकारियों द्वारा ट्रिब्यूनल द्वारा पारित दिनांक 18.6.2012 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को नकार दिया गया था। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा की गई शिकायत का किसी भी सक्षम मंच द्वारा समाधान नहीं किया गया। उनकी शिकायत का निपटारा कानून के मुताबिक किया जाना चाहिए।' अपीलकर्ता को तीन महीने के भीतर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई है। [पैरा 35] [443-जी-एच; 444-ए-बी)

आर. विस्वान एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य [1983] 3 एससीआर 60: (1983) 3 एससीसी 401; भारत संघ एवं अन्य बनाम सुनील कुमार सरकार (2001) 3 एससीसी 414; एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ [1997] 2 एससीआर 1186: (1997) 3 एससीसी 261; भारत संघ बनाम जीएस ग्रेवाल (2014) 7 एससीसी 303; सब-इंस्पेक्टर रूपलाल बनाम लिमिटेड गवर्नर [1999] 5 पूरक एससीआर 310 : (2000) 1 एससीसी 644 – संदर्भित।

प्रकरण कानून संदर्भ

[1983] 3 एससीआर 60 संदर्भित किया गया पैरा 4

(2001) 3 एससीसी 414 संदर्भित किया गया पैरा 5

[1997] 2 एससीआर 1186 संदर्भित किया गया पैरा 19

(2014) 7 एससीसी 303 संदर्भित किया गया पैरा 26

[1999] 5 पूरक एससीआर 310 संदर्भित किया गया पैरा 27

[1993] 1 एससीआर 1113 भरोसा व्यक्त किया पैरा 34

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 10131/2016

रिट याचिका (सी) संख्या 4074/2012 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 02.08.2013 से।

सुश्री प्रिया हिंगोरानी, राजेश के. सिंह, आर. वी. कामेश्वरन, अधिवक्तागण, अपीलकर्ता के लिए।

सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, सुश्री माधवी दीवान, रश्मी मल्होत्रा, आर.के. राठौड़, आर.एस. नागर, सुश्री निधि खन्ना, डी.एस. महरा, सुश्री सिंधा मेहरा, अधिवक्तागण प्रतिवादीगणो के लिए।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

1. अपीलकर्ता को भारत सरकार, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवाओं (बीआरईएस) में दिनांक 03.06.1985 के आदेश के तहत सहायक कार्यकारी अभियंता (ई एंड एम) के रूप में नियुक्त किया गया था। उचित समय पर, उन्हें 30.05.1997 को कार्यकारी अभियंता (ई एंड एम) के पद पर पदोन्नत किया गया और उसके बाद रुपये 12000-375-16500/- के वेतनमान में उनके पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी सीमा सड़क संगठन के जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स (जीआरईएफ) में अधीक्षण अभियंता (ई एंड एम) के ग्रेड पर पदोन्नत किया गया। अपेक्षित वर्षों से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद अपीलकर्ता को संगठित के अधिकारियों ग्रुप –ए के लिए गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन प्रदान नहीं किया गया और इसने उन्हें संबंधित अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए मजबूर किया, लेकिन इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उन्होंने दो साल की निर्धारित कमांड पोस्टिंग को पूरा नहीं किया है। उक्त संचार से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने केंद्रीय

प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी पीठ, गुवाहाटी के समक्ष मूल आवेदन संख्या 102 / 2012 प्रस्तुत किया।

2. प्रतिवादी ने न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति दायर की। न्यायाधिकरण ने दिनांक 18.06.2012 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में मामले का फैसला किया। ट्रिब्यूनल ने रामकली मिश्रा एवं अन्य भारत संघ लखनऊ बेंच द्वारा पारित मामले में अपने फैसले का हवाला दिया, जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया है: -

> "9. ऊपर जो चर्चा की गई है, उसके अनुसार, आवेदक, जो जीआर.ई.एफ. का सीधे तौर पर भर्ती किया गया कार्मिक है, 1965 के नियमों द्वारा शासित होता है, उन अधिकारों को छोड़कर जो एसआरओ 329 द्वारा प्रतिबंधित हैं जैसा कि एसआरओ 364 और 330 द्वारा संशोधित धारा के तहत जारी किया गया है 1950 के अधिनियम के 4 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 33 के साथ पढ़ें, इसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायाधिकरण के पास 1965 के नियमों के तहत आवेदक के खिलाफ पारित निष्कासन आदेश के खिलाफ दायर वर्तमान ओए पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।"

इस दृष्टिकोण के चलते ट्रिब्यूनल ने राय दी कि मूल आवेदन पर विचार करना उसके अधिकार क्षेत्र में है।

3. ट्रिब्यूनल के आदेश से असंतुष्ट, प्रतिवादीगण ने डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 4074/2012 को प्राथमिकता देते हुये ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 2.8.2013 के आक्षेपित आदेश द्वारा निम्नलिखित प्रश्न उठाया:

> "क्या जीआरईएफ के एक सदस्य को सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि, ऐसे सदस्य को, यदि कानून में, सशस्त्र बलों

के सदस्य के रूप में माना जाता है, तो, प्रावधान, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 में सन्निहित होंगे, ऐसे सदस्य के लिए उपलब्ध नहीं होंगे?"

4. उच्च न्यायालय ने आर. विस्वान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य' मामले में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया, उक्त प्राधिकारी के विभिन्न अंशों को पुन: प्रस्तुत किया और 1995 के एसएलपी (सी) संख्या 8096 (भारत संघ बनाम श्रीमती विद्यावती) में पारित आदेश भी दिया और इस प्रकार लागू हुआ: -

> "विद्यावती के मामले (उपरोक्त) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में, कोई भी निष्कर्ष से बच नहीं सकता है, और हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, कि जहां तक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का संबंध है, जीआरईएफ का एक सदस्य विद्यावती के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के साथ पढ़े गए आर. विस्वान (सुप्रा) के निर्णय के आलोक में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के प्रावधानों द्वारा कवर नहीं किया गया है, और, इसलिए, जीआरईएफ का एक सदस्य केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से वंचित होगा।"

5. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या जीआरईएफ का सदस्य सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 (संक्षिप्तता के लिए, "2007 अधिनियम") में सन्निहित प्रावधानों के अंतर्गत आता है। न्यायालय ने सेना अधिनियम, 1950 (संक्षेप में, "1950 अधिनियम") के प्रावधानों, 2007 अधिनियम में निहित प्रावधानों, केंद्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण और अपील) नियम, 1965, के प्रावधानो का उल्लेख किया, भारत संघ और अन्य बनाम सुनील कुमार सरकार के आदेश में, और अंततः निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे:-

"32. उपरोक्त चर्चा से जो बात सामने आती है वह यह है कि वर्तमान प्रतिवादी, जीआरईएफ के सदस्य और सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में, आर. विस्वान (उपरोक्त) के निर्णय के आलोक में विद्यावती के मामले में (उपरोक्त) निर्णय के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के प्रावधानों का सहारा नहीं ले सकता था। नतीजतन, विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास याचिकाकर्ता (यानि कि वर्तमान प्रतिवादी) के मामले में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। वित्तीय उन्नयन देने से इनकार करने के संबंध में शिकायत और साथ ही, प्रतिवादी की शिकायत से पता चलता है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भी उसे वित्तीय उन्नयन देने से इनकार करने के संबंध में उसकी शिकायत का निवारण नहीं कर सकता था। इसलिए, प्रतिवादी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में उचित आवेदन करना होगा, या अपनी शिकायतों के समाधान के लिए उचित मुकदमा दायर करना होगा।"

6. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता की विद्वान वकील सुश्री प्रिया हिंगोरानी ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि उठाई गई शिकायत की प्रकृति केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णय योग्य है और एक तथ्य के रूप में क्षेत्राधिकार के मुद्दे को निर्धारित करने के बाद, जिसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में उठाया गया था, न्यायाधिकरण विवाद से निपटा है और राहत दी है जो निर्विवाद रही है और ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करने से इनकार कर देना चाहिए था. विद्वान वकील आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा आर. विस्वान (उपरोक्त) और सुनील कुमार सरकार (उपरोक्त) के आदेशो पर निर्भरता अनुचित प्रशंसा पर आधारित है, क्योंकि अपीलकर्ता का दावा बिल्कुल अलग है। इसके अतिरिक्त, यह आग्रह किया जाता है

कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र की कमी के संबंध में चित्रण भ्रामक तर्क से ग्रस्त है। अंत में, यह प्रचारित किया जाता है कि यह न्यायालय अंततः मंच का निर्धारण कर सकता है और अपीलकर्ता को अपने उपचार के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है, क्योंकि वह आंदोलन के लिए मंच के बिना कोई शिकायत नहीं कर सकता है।

7. आगे यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय 6 जून, 2012 को सीमा सड़क महानिदेशक के कार्यालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण परिपत्र के प्रभाव और प्रभाव की सराहना करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा एक अनिश्चित दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना आवश्यक है।

8. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री पिंकी आनंद का तर्क है कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के कर्मचारियों से संबंधित मामलों पर ध्यान देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो सीमा सड़क विकास बोर्ड (बीआरडीबी) का एक भाग का गठन करता है। उनका कहना है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास एसआरओ 329 और 330 के तहत दिए गए अपवादों के संदर्भ में अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो सरकार द्वारा 1950 अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। यह बताया गया है कि ये अपवाद और ये अपवाद कुछ मामलों में जीआरईएफ को 1950 अधिनियम के दायरे से बाहर करते हैं जो सेवा मामलों से संबंधित हैं। उस आधार पर, विद्वान वकील आग्रह करेंगे कि 2007 अधिनियम की धारा 2(1) हालांकि 1950 अधिनियम के अधीन सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, फिर भी एसआरओ 329 और 330 में प्रयुक्त भाषा, सेवा से संबंधित मामलों को ध्यान में रखा जाता है। जीआरईएफ की शर्तें केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 1965 द्वारा शासित होंगी। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि यह केवल उच्च न्यायालय

है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सेवा विवाद से संबंधित मामलों पर विचार कर सकता है।

9. इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवाओं में जीआरईएफ का सदस्य है। आर. विस्वान (उपरोक्त) में, संविधान पीठ संविधान के अनुच्छेद 33 की व्याख्या में लगी हुई थी और इस मुद्दे के साथ कि क्या 1950 अधिनियम की धारा 21 सपठित सेना नियम, 1954 के अध्याय IV, अनुच्छेद 33 के दायरे और परिधि में है और, यदि ऐसा है, तो क्या केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या एसआरओ 329 और 330 दिनांक 23 सितंबर, 1960, अन्य बातों के अलावा, 1950 अधिनियम की धारा 21 और सेना नियम, 1954 का अध्याय IV जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स पर लागू होते हैं। यह अनुच्छेद अधिकारातीत है क्योंकि जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स न तो एक सशस्त्र बल है और न ही सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार बल है। इससे निपटने वाली बड़ी पीठ ने जीआरईएफ के प्राथमिक कार्यों, 1950 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया और राय दी कि जहां तक जीआरईएफ के कर्मियों का सवाल है, वे आंशिक रूप से सेना से और आंशिक रूप से सीधी भर्ती से आते हैं। सेना के जवानों को जीआरईपी में एक सोची-समझी और सावधानीपूर्वक नियोजित मैनिंग नीति के अनुसार तैनात किया जाता है, जो सेना को उसकी परिचालन आवश्यकताओं में सहायता करने के उद्देश्य से एक बल के रूप में जीआरईएफ के विशेष चरित्र को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकसित की गई है। जीआरईएफ इकाइयों में सेना कर्मियों की पोस्टिंग वास्तव में सामान्य रेजिमेंटल पोस्टिंग के रूप में मानी जाती है और इस प्रकार तैनात सेना कर्मियों को किसी भी प्रतिनियुक्ति या अन्य भत्ते का अधिकार नहीं मिलता है और इसे पदोन्नति, कैरियर योजना आदि के उद्देश्य से सेना में समान पोस्टिंग के बराबर माना जाता है। जीआरईएफ इकाइयों में तैनात सेना कर्मियों के कार्यकाल को सामान्य रेजिमेंटल ड्यूटी के रूप में माना जाता है और ऐसे सेना कर्मी 1950 अधिनियम

और जीआरईएफ में रहते हुए सेना नियम, 1954 के प्रावधानों के अधीन रहते हैं। न्यायालय ने आगे फैसला सुनाया कि सेना के जवान जो जीआरईएफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, यहां तक कि सीधे भर्ती किए गए कर्मी जो सेना से नहीं आते हैं, उन्हें जीआरईएफ के विशेष चरित्र और इसकी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए सख्त सेना अनुशासन के अधीन किया जाता है। अपनी परिचालन आवश्यकताओं में सेना के समर्थन में खेलने के लिए। चूंकि शत्रुता के फैलने की स्थिति में जीआरईएफ इकाइयों की क्षमता और दक्षता उनकी सभी समय की क्षमता और दक्षता पर निर्भर करती है, इसलिए उन्हें शांति काल के दौरान भी कठोर अनुशासन के अधीन किया जाता है, क्योंकि यह प्राथमिक है कि उनसे इस अवसर पर अचानक उठने और सैन्य अभियानों के दौरान सेना को आवश्यक सहायता प्रदान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जब तक कि वे हर समय उचित रूप से अनुशासित और फिट स्थिति में न हों ताकि किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें।

10. 1950 अधिनियम की धारा 29 की संवैधानिक वैधता पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने उक्त अधिनियम और सेना नियम 1954 के तहत जारी एसआरक्यू 329 और 330 पर विचार-विमर्श किया और इस प्रकार व्यक्त किया: -

> "जीआरईएफ का इतिहास, संरचना, प्रशासन, संगठन और भूमिका जो हमने तथ्यों को बताते हुए ऊपर वर्णित की है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जीआरईएफ सशस्त्र बलों का एक अभिन्न अंग है। यह निस्संदेह एक विभागीय निर्माण एजेंसी है जैसा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है लेकिन यह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग आदि जैसी अन्य निर्माण एजेंसियों से अलग है क्योंकि यह एक ऐसा बल है जिसका मुख्य उद्देश्य सेना को उसकी परिचालन आवश्यकताओं में सहायता करना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीमा सड़क संगठन, जो जीआरईएफ

के समग्र नियंत्रण में है मूल रूप से सेना मुख्यालय के हिस्से के रूप में बनाया गया था और बाद में, उच्च नीति के कारणों से, इसे सेना मुख्यालय से अलग कर दिया गया और सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत रखा गया।"

11. आगे विस्तार से बताते हुए, संविधान पीठ ने कहा कि जीआरईएफ इकाइयां अनिवार्य रूप से उन कार्यों को करती हैं जो अन्यथा सेना इंजीनियरिंग रेजिमेंट द्वारा किए जाते हैं और वे शांति के समय और शत्रुता के दौरान भी सेना को इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करते हैं। सेवा की शर्तों और विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रशिक्षण में न केवल ड्रिल, मार्चिंग और सैल्यूटिंग शामिल है, बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण जैसे खड़े होकर अभ्यास, बीम अभ्यास, रस्सी का काम, रूट मार्च इत्यादि और युद्ध इंजीनियरिंग भी शामिल है। प्रशिक्षण में फील्ड इंजीनियरिंग, सेवा विस्फोटकों का संचालन, छलावरण, लड़ाकू उपकरण, ब्रिजिंग, फील्ड किलेबंदी, तार बाधाएं आदि शामिल हैं। इसके अलावा, सीधे भर्ती किए गए कर्मियों को केवल तभी लिया जाता है जब वे स्वेच्छा से रोजगार के नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शर्तें 5(iv), 5(v), 5(vi) और 5(xi) शामिल हैं और उक्त शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि सीधे भर्ती किए गए कर्मियों को भारत में और भारत के बाहर कहीं भी सेवा करने की आवश्यकता हो सकती है और जब निर्देश दिया जाएगा, तो वे ऐसा करेंगे। फील्ड सेवा पर आगे बढ़ना होगा और यदि आवश्यक हो, तो वे भारत की रक्षा से जुडी किसी भी रक्षा सेवा या पद पर सेवा करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि इन शर्तों में यह भी निर्धारित है कि उनकी नियुक्ति पर, सीधे भर्ती किए गए कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी पहननी होगी और वे 1950 अधिनियम और सेना नियम, 1954 के प्रावधानों के अधीन होंगे। जैसा कि अनुशासन के प्रयोजनों के लिए एसआरओ संख्या 329 और 330 में निर्धारित किया गया है और इसलिए, यह

बिल्कुल स्पष्ट है कि जीआरईएफ सशस्त्र बलों का एक अभिन्न अंग है और जीआरईएफ के सदस्यों को वैध रूप से संविधान के अनुच्छेद 33 के अर्थ के भीतर सशस्त्र बलों का सदस्य कहा जा सकता है।

12. सुनील कुमार सरकार (उपरोक्त) में सीमा सड़क संगठन को धोखा देने के कुछ आरोपों के लिए प्रतिवादी के खिलाफ 1950 अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक सामान्य कोर्ट मार्शल शुरू किया गया था, जिसमें वह अधीक्षक, भवन और सड़क, ग्रेड II के रूप में काम कर रहे थे। कार्यवाही के समापन पर, उन्हें दोषी पाया गया और एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की गई। उक्त अवधि के दौरान, 1965 के नियमों के नियम 19 के तहत कार्य करने वाले अधिकारियों ने कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके खिलाफ उचित आदेश पारित किया जाए। उक्त विभागीय जांच के निष्कर्ष पर प्राधिकारी ने प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। प्रतिवादी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को सफलता नहीं मिली। 1950 अधिनियम के तहत दोषसिद्धि और सेना नियमों के तहत बर्खास्तगी को एक रिट याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को अनुमति देते हुए अधिकारियों को कारणों सहित एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश को इंट्रा-कोर्ट अपील में चुनौती दी गई थी और डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए अपील की अनुमति दी थी कि कोर्ट मार्शल की कार्यवाही के साथ-साथ उसके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही दूषित थी। इस न्यायालय ने, भारत संघ द्वारा दायर किए जाने पर, अपील की अनुमति दी और डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द कर दिया। हालाँकि, उस संदर्भ में यह देखा गया कि तर्क के दौरान, अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ शुरू की गई समवर्ती कार्यवाही की स्थिरता के बारे में संदेह उठाया गया था, क्योंकि प्रतिवादी को 1950 के अधिनियम के तहत उसी कदाचार के लिए दंडित किया गया था। और जैसा

कि 1965 के नियमों के तहत भी है और ऐसी स्थिति में, यह दोहरा ख़तरा होगा और इस तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। उक्त पहलू से निपटते हुए, न्यायालय ने कहा:-

> "इस संबंध में संबोधित तर्कों पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि जहां तक सेना अधिनियम और केंद्रीय नियमों दोनों के तहत प्रतिवादी के खिलाफ संगठन द्वारा शुरू की गई समवर्ती कार्यवाही का संबंध है, वे अपवाद योग्य नहीं हैं। ये दो कार्यवाही संचालित होती हैं हालांकि अपराध या कदाचार एक ही कार्य से दो अलग-अलग क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं। कोर्ट-मार्शल कार्यवाही कदाचार के दंडात्मक पहलू से निपटती है जबकि केंद्रीय नियमों के तहत कार्यवाही कदाचार के अनुशासनात्मक पहलू से निपटती है। दो कार्यवाहियां ओवरलैप नहीं होती हैं। वास्तव में, केंद्रीय नियमों के तहत और सेना अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) और (4) के तहत जारी अधिसूचना संख्या एसआरओ-329 दिनांक 23-9-1960 इस स्थिति को स्पष्ट करती है। इस अधिसूचना के द्वारा केंद्रीय नियमों के तहत मिलने वाली सज़ाओं को सेना अधिनियम के तहत कोर्ट-मार्शल कार्यवाही के दायरे से बाहर कर दिया गया है। हमें आर. विस्वान बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय के फैसले में अपने इस दृष्टिकोण का समर्थन मिलता है।"

13. उपरोक्त निर्णय यह स्पष्ट करता है कि 1950 अधिनियम के साथ-साथ 1965 नियमों के तहत कार्यवाही कायम है और दोहरे खतरे की श्रेणी में नहीं आती है। सिद्धांत यह है कि 1950 के अधिनियम के तहत उस समय व्यथित व्यक्ति उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और इसी तरह, अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत सजा दिए जाने से व्यथित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दे

सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने यह नहीं सोचा कि पीड़ित पक्ष 1985 अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है।

14. इस संबंध में, हम 1950 अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी एसआरओ 329 का उल्लेख कर सकते हैं। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

> "एसआरओ 329 दिनांक 23-9-1960
>
> सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा:
>
> (ए) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स पर लागू होता है, जो केंद्र सरकार के अधिकार के तहत भारत में गठित और बनाए रखा गया बल है, अनुसूची बी में निर्धारित संशोधनों के अधीन अनुसूची ए में दिखाए गए प्रावधानों को छोड़कर उक्त अधिनियम के सभी प्रावधान; और
>
> (बी) निर्देश देता है कि अनुसूची 'सी' के पहले कॉलम में उल्लिखित अधिकारी अपने आदेश के तहत उक्त बल के सदस्यों के संबंध में उक्त अधिनियम के संचालन के लिए प्रासंगिक अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन करेंगे, जो कि उसके दूसरे कॉलम में निर्दिष्ट हैं।"

15. उपरोक्त परिपत्र में कुछ अपवाद बताए गए हैं। इन अपवादों में विशेष रूप से सेवा मामलों से संबंधित कुछ मामलों में 1950 अधिनियम के दायरे से जीआरईएफ शामिल है। विवाद की सराहना करने के लिए, उन अपवादों का उल्लेख करना उचित है जो अनुसूची ए में शामिल हैं। वे इस प्रकार पढ़ते हैं: -

"शैडॅयल - ए

अपवाद

धाराये 10, 11, 13 से 17, 20, 22 से 24, 43, 44 धारा 71 के खंड (डी), (ई), (एफ), (जी) और (के), 74 से 78 खंड (ई), धारा 80 के (एफ) और (जे) और धारा 84 के खंड (ए)।"

उपरोक्त अपवाद स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि 1950 का अधिनियम जीआरईएफ के सदस्यों पर संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है।

16. इस संबंध में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 2(ए) को पुन: प्रस्तुत करना उचित है, जो इस प्रकार है:-

> "2. अधिनियम का कुछ व्यक्तियों पर लागू न होना: इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे-
>
> (ए) नौसेना, सैन्य या वायु सेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का कोई भी सदस्य;"

17. प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 3 (क्यू), जो भी प्रासंगिक है, नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है: -

> "3(क्यू) "सेवा मामले", किसी व्यक्ति के संबंध में, संघ या किसी राज्य या भारत के क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के मामलों के संबंध में उसकी सेवा की शर्तों से संबंधित सभी मामले हैं। या भारत सरकार के नियंत्रण में, या, जैसा भी मामला हो, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या सोसायटी के संबंध में-
>
> (i) पारिश्रमिक (भत्तों सहित), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ;

(ii) पुष्टिकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति सहित कार्यकाल;

(iii) किसी भी प्रकार की छुट्टी;

(iv) अनुशासनात्मक मामले, या

(v) कोई अन्य मामला जो भी हो,"

18. दोनों प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह ध्यान देने योग्य है कि प्रावधानों की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है और अधिनियम सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य पर लागू नहीं होता है और इसलिए, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित है कि केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के पास विवाद से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस संबंध में, विद्यावती (उपरोक्त) के मामले में 9 जनवरी, 1998 को पारित आदेश पर भरोसा किया गया है: -

> "जैसा कि हमें प्रतीत होता है कि जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के सदस्य आर. विस्वान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (एआईआर 1983 एससी 558) मामले में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का रुख नहीं कर सकते हैं, कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसलिए इसे रद्द कर दिया गया है। हालाँकि, प्रतिवादी को स्वतंत्रता दी गई है कि यदि प्रतिवादी चाहे तो उचित राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है। यदि ऐसी रिट याचिका दायर की जाती है, तो इसकी सराहना की जाएगी यदि प्रतिवादी के वृद्ध विधवा होने को ध्यान में रखते हुए वह उच्च न्यायालय शीघ्र ही इसका निपटान कर देता है।"

19. ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय ने उसी पर भरोसा किया है। इसमें एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला दिया गया है, लेकिन हमें लगता है कि इसे बढ़ावा देना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने प्रश्नगत मामले से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं दिया गया है।

20. अगला मुद्दा जो विचार के लिए उभरता है वह यह है कि क्या 2007 अधिनियम के लागू होने के बाद, यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण होगा जो विवाद से निपटेगा या उच्च न्यायालय के पास अभी भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मूल क्षेत्राधिकार रहेगा। 2007 अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्पष्ट रूप से बताता है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का गठन सेवा मामलों और सदस्यों के कोर्ट-मार्शल के फैसलों से उत्पन्न अपीलों से संबंधित शिकायतों और विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया है: तीन सेवाएं (सेना, नौसेना और वायु सेना) को संघ के उक्त सशस्त्र बलों के सदस्यों को शीघ्र कम खर्चीला न्याय प्रदान करना है। धारा 2 जो 2007 अधिनियम की प्रयोज्यता से संबंधित है, इस प्रकार है: -

> "2. अधिनियम की प्रयोज्यता: (1) इस अधिनियम के प्रावधान सेना अधिनियम, 1950, (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अधीन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।
>
> (2) यह अधिनियम सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अधीन सेवानिवृत्त कर्मियों पर भी लागू होगा, जिसमें उनके आश्रित, वारिस और उत्तराधिकारी भी शामिल हैं, जहां तक यह उनके सेवा मामलों से संबंधित है।"

21. 2007 अधिनियम की धारा 3(0) सेवा मामलों के संबंध में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। यह इस प्रकार है:-

"3(0) "सेवा मामले", सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अधीन व्यक्तियों के संबंध में , मतलब उनकी सेवा की शर्तों से संबंधित सभी मामले और इसमें शामिल होंगे-

(i) पारिश्रमिक (भत्तों सहित), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ;

(ii) कार्यकाल, जिसमें कमीशन, नियुक्ति, नामांकन, परिवीक्षा, पुष्टिकरण, वरिष्ठता, प्रशिक्षण, पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, समय से पहले सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति और दंडात्मक कटौती शामिल है;

(iii) संक्षिप्त निपटान और परीक्षण जहां बर्खास्तगी की सजा दी जाती है;

(iv) कोई भी अन्य मामला, जो भी हो,

लेकिन इसमें निम्नलिखित से संबंधित मामले शामिल नहीं होंगे-

(i) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 15 की उप-धारा (1) और वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 18 (1950 का 45) के तहत जारी किए गए आदेश; और

(ii) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अधीन व्यक्तियों के संबंध में स्थानांतरण और पोस्टिंग, जिसमें पोस्टिंग पर स्थान या यूनिट का परिवर्तन शामिल है, चाहे व्यक्तिगत रूप से या यूनिट, गठन या जहाज के हिस्से के रूप में।

(ii) किसी भी प्रकार की छुट्टी;

(iv) समरी कोर्ट मार्शल, सिवाय इसके कि जहां सजा बर्खास्तगी या तीन महीने से अधिक की कैद की हो;

22. 2007 अधिनियम की धारा 14 न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार, शक्ति और प्राधिकार से संबंधित है, जिसे नीचे दिया गया है: -

"14. सेवा मामलो में क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और प्राधिकार - (1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, न्यायाधिकरण, नियत दिन से, उस दिन से ठीक पहले प्रयोग किए जाने वाले सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा सभी सेवा मामलों के संबंध में अदालतें (संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर)।

(2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, किसी भी सेवा मामले से संबंधित आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे प्रारूप में और ऐसे दस्तावेजों या अन्य सबूतों के साथ और ऐसी फीस के भुगतान पर ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकता है जैसा कि निर्धारित किया जाये।

(3) सेवा मामलों से संबंधित एक आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायाधिकरण, यदि उचित जांच के बाद संतुष्ट हो जाता है, जैसा कि वह आवश्यक समझ सकता है, कि यह उसके द्वारा न्यायनिर्णयन के लिए उपयुक्त है, तो ऐसे आवेदन को स्वीकार करेगा; लेकिन जहां ट्रिब्यूनल इतना संतुष्ट नहीं है, वह लिखित में कारण दर्ज करने के बाद आवेदन को खारिज कर सकता है।

(4) xxxxxxxxxx"

(5) xxxxxxxxxx"

23. 2007 अधिनियम की धारा 2 में प्रयुक्त भाषा यह बताती है कि यह 1950 अधिनियम के अधीन लागू होगी। 1950 अधिनियम की धारा 4 अध्याय II में आती है जो 'कुछ मामलों में अधिनियम के आवेदन के लिए विशेष प्रावधान' शीर्षक के अंतर्गत आती है, जो इस प्रकार है: -

"4. केंद्र सरकार के अधीन कुछ बलों पर अधिनियम का लागू होना.-(1) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी प्रावधान को संशोधनों के साथ या बिना किसी भी बल पर लागू कर सकती है और उस सरकार के अधिकार के तहत भारत में बनाए रखा जाता है, और उक्त बल पर लागू होने वाले किसी भी अन्य अधिनियम के संचालन को निलंबित कर दिया जाता है।

(2) इस प्रकार लागू किए गए इस अधिनियम के प्रावधान उक्त बल से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे नियमित सेना में उपरोक्त व्यक्तियों के समान या समकक्ष रैंक रखने वाले इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों के संबंध में होते हैं फिलहाल उक्त बल में।

(3) इस प्रकार लागू किए गए इस अधिनियम के प्रावधान उन व्यक्तियों के संबंध में भी प्रभावी होंगे जो उक्त बल के किसी भी हिस्से में कार्यरत हैं या उसकी सेवा में हैं या उसके अनुयायी हैं या उसके साथ हैं यह अधिनियम धारा (2) की उपधारा (1) के खंड (i) के अंतर्गत है।

(4) जबकि इस अधिनियम के कोई भी प्रावधान उक्त बल पर लागू होते हैं, केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि इन प्रावधानों के संचालन उक्त बल के लिए किसी भी क्षेत्राधिकार, शक्तियों या कर्तव्यों का किस प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या पालन किया जाएगा।

24. 2007 अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जैसा कि स्पष्ट है, सशस्त्र बलों के सदस्यों के सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों और विवादों के न्यायनिर्णयन का आदेश देता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जीआरईएफ के सदस्य सशस्त्र बलों से संबंधित हैं। जीआरईएफ के संविधान, जैसा कि इस न्यायालय ने समझा है, की सराहना की जानी चाहिए। यह एक विभागीय निर्माण एजेंसी है जो देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी आदि जैसी अन्य निर्माण एजेंसियों से अलग है, क्योंकि यह केंद्रीय सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में परिचालन भूमिका में सेना का की सहायता करने के लिये गठित और रखरखाव किया जाने वाला एक बल है। जीआरईएफ सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत कार्य करता है, और इसकी इकाइयां सेना इकाइयों/उप इकाइयों जैसे टास्क फोर्स, सड़क निर्माण कंपनियों, सड़क रखरखाव प्लाटून आदि की तर्ज पर तैयार की जाती हैं।

25. मौजूदा विवाद की सराहना करने के लिए, यह समझना जरूरी है कि आर. विस्वान (उपरोक्त) में क्या रखा गया है। संविधान पीठ के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या जीआरईएफ के सदस्यों को अनुच्छेद 33 के अर्थ के तहत सशस्त्र बलों का सदस्य कहा जा सकता है ताकि 1950 अधिनियम की धारा 21 को उन पर लागू किया जा सके और बड़ी पीठ ने, जैसा कि पहले कहा है, माना कि चूंकि अनुशासन के मामलों में जीआरईएफ के सदस्य 1950 अधिनियम और सीसीएस (सीसीए) नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं, इसलिए, इसे विवेक पर छोड़ दिया जाएगा। प्राधिकारी ने कर्मचारी के खिलाफ 1950 अधिनियम के तहत या सीसीएस (सीसीए) नियमों के तहत कार्रवाई की है या नहीं और इस आधार पर विवाद को खारिज कर दिया कि दोनों के तहत कार्यवाही की प्रकृति अलग-अलग है, पहला दंडात्मक है और दूसरा केवल अनुशासनात्मक है। इसलिए, आर. विस्वान (उपरोक्त) इस हद तक एक प्राधिकारी हैं कि जीआरईएफ के सदस्यों को हालांकि नागरिक अधिकारी कहा जा सकता है, फिर भी संगठन की प्रकृति के

अनुसार, उन्हें अर्थ के भीतर सशस्त्र बलों का एक अभिन्न अंग माना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत और 1950 अधिनियम और सेना नियम, 1954 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई और सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

26. इस संबंध में, भारत संघ बनाम जीएस ग्रेवाल' में प्राधिकरण का उल्लेख करना उपयुक्त है। उक्त मामले में, प्रतिवादी, जो सेना में मेजर है, को अगले उच्च ग्रेड यानी लेफ्टिनेंट कर्नल में पदोन्नति के लिए विचार किया गया था, लेकिन निर्दिष्ट प्रयासों के बाद भी उसे पदोन्नत नहीं किया जा सका। अंततः उन्हें सेना से हटा दिया गया और उसके बाद गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) में शामिल हो गए और वहां उन्हें अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया। डीजीक्यूए में दिनांक 04.05.1993 के ओएम के माध्यम से एक प्रावधान था कि सेना में अंततः पदावनत किया गया कोई अधिकारी स्थायी पद पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, सेना में, 'ए.वी. सिंह समिति' नामक एक रिपोर्ट के अनुसार मेजर रैंक वाले सभी अधिकारी, जिन्होंने 13 साल की सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, भले ही ऐसे अधिकारियों को अंततः हटा दिया गया हो या नहीं। प्रतिवादी को 16.12.2004 को लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया था। हालाँकि, सरकार के आदेश पर 12.10.2007 को उक्त नीति बंद कर दी गई थी। स्थायी सेकेंडमेंट और पदोन्नति के लिए 16.11.2007 को एक नीति जारी की गई थी, जिसमें प्रावधान किया गया था कि स्थायी सेकेंडमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक ही सीमित रहेगा और यह भी कि एक बार स्थायी रूप से सेकेंड किए गए अधिकारी सेवानिवृत्त होने तक संगठन में बने रहेंगे और उनकी रिक्तियों के विरुद्ध उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए भी विचार किया जाएगा। प्रतिवादी को 10.04.2008 को डीजीक्यूए में स्थायी रूप से नियुक्त किया गया था और 22.10.2008 को डीजीक्यूए में कर्नल के पद पर उसकी अगली पदोन्नति भी हुई। हालाँकि, रक्षा मंत्रालय ने

23.04.2010 यह कहते हुये एक आदेश जारी किया कि चूंकि सेना में पदोन्नति की नीति बंद कर दी गई थी, इसका प्रभाव डीजीक्यूए में 1993 की पिछली नीति की बहाली था और इस प्रकार, वर्ष 2006 में सेना में नीति को बंद करने के बाद कोई स्थायी सेकेंडमेंट नहीं दिया जा सकता था। इसके अलावा यह प्रावधान किया गया था कि पहले से दिया गया स्थायी सेकेंडमेंट वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन आगे ऐसे अधिकारियों को कोई पदोन्नति नहीं दी जाएगी। यह वह आदेश था जिसका सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष सफलतापूर्वक विरोध किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष, दो तर्क थे, अर्थात्, (i) ट्रिब्यूनल लंबित पर विचार नहीं कर सकता था क्योंकि ट्रिब्यूनल की एक समन्वय पीठ ने एक निर्णय दिया था जिसमें कहा गया था कि इसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, और (ii) डीजीक्यूए द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, जो एक नागरिक संगठन है, ट्रिब्यूनल के पास मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, उठाए गए थे।

27. हालांकि न्यायालय ने मामले को मुख्य रूप से उप में निर्धारित कानून के आधार पर वापस भेज दिया। इंस्पेक्टर रूपलुल बनाम लिमिटेड गवर्नर, फिर भी निर्णय के पैरा 26 में, प्रश्नकर्ता पर विचार किया गया कि 1950 अधिनियम और सेना नियमों के अधीन अधिकारियों के मामलों में न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार पर विचार करने में क्या निर्णायक होगा। इसे निम्नानुसार देखा गया:-

> "हम यह बता सकते हैं कि केवल इसलिए कि प्रतिवादी सेना अधिनियम के अधीन है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि ट्रिब्यूनल के पास ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके सामने लाए गए किसी भी मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र है। यह विषय पर निर्भर करेगा- जो मामला ट्रिब्यूनल के समक्ष लाया जाता है और ट्रिब्यूनल को यह निर्धारित करने की भी आवश्यकता होती है कि क्या ऐसा विषय-वस्तु "सेवा मामलों" की परिभाषा में आता है, जैसा कि एएफटी अधिनियम की धारा 3 (0) में निहित है। मेजर जनरल एस.बी. अकाली के प्रकरण

में मामले में, प्रधान पीठ मुख्य रूप से इस पर विचार कर रही थी। विषय-वस्तु लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति थी और यह पदोन्नति डीआरडीओ की नीति में निहित नियमों द्वारा शासित थी, न कि सेना अधिनियम के तहत। इसलिए, वर्तमान मामले में, इस बात की जांच करना आवश्यक है कि क्या दावा की गई राहत पूरी तरह से डीजीक्यूए या रक्षा मंत्रालय के क्षेत्र में है या इसे अभी भी एएफटी की धारा 3 (0) के तहत "सेवा मामला" माना जा सकता है। अधिनियम और दो पहलू एक दूसरे के साथ गुंथे हुए और अविभाज्य रूप से मिश्रित हैं। इस तरह का अभ्यास दोनो पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो के आधार पर लिया जाना है। ऐसा नहीं किया गया है। इस कारण से, हम इन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मामले को ट्रिब्यूनल को वापस भेजना उचित समझते हैं।"

28. इस प्रकार, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि केवल इसलिए कि प्रतिवादी 1950 अधिनियम के अधीन है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि न्यायाधिकरण के पास ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष लाए गए किसी भी मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र है। यह उस विषय वस्तु पर निर्भर करेगा जिसे ट्रिब्यूनल के समक्ष लाया गया है और ट्रिब्यूनल को यह निर्धारित करने की भी आवश्यकता है कि क्या ऐसा विषय 2007 अधिनियम की धारा 3 (0) में निहित "सेवा सामग्री" की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं।

29. इस समय, एसआरओ 329 का उल्लेख करना उचित है। इसकी अनुसूची ए, जैसा कि पहले कहा गया है, कुछ अपवादों को उजागर करती है। 1950 अधिनियम के कुछ प्रावधान यानी धारा 10, 11, 13 से 17, 20, 22 से 24 [कमीशन, नियुक्ति और नामांकन से संबंधित 1950 अधिनियम के अध्याय III के अंतर्गत आते हैं], धारा 43, 44 [अध्याय VI के अंतर्गत आते हैं- अपराध ' अर्थात. फर्जी नामांकन और नामांकन पर गलत उत्तर क्रमशः और धारा

71, 74 से 78 के खंड (डी), (ई), (एफ), (जी) और (के), धारा के खंड 9 ई), (एफ) और (जे) 80 और धारा 84 के खंड (ए), जो अध्याय VII-सज़ा के अंतर्गत आते हैं] को जीआरईएफ के नागरिक सदस्यों के लिए उनके आवेदन में छूट दी गई है, क्योंकि जीआरईएफ के नागरिक कर्मियों को 1950 अधिनियम के तहत कमीशन या नामांकित या नियुक्त नहीं किया गया है और वे इसलिए, 1950 अधिनियम की धारा 3(xxi) में परिभाषित 'नियमित सेना' के सदस्य नहीं हैं। यही कारण है कि एसआरओ 329 की अनुसूची बी में निर्धारित 1950 अधिनियम के कुछ प्रावधानों को जीआरईएफ के सदस्यों के लिए उनके आवेदन में संशोधित किया गया है। यह इस तथ्य से मजबूत होता है कि जीआरईएफ कर्मियों को जीआरईएफ में विभिन्न नियुक्तियों/पदनामों में बल के नागरिक घटक के रूप में नियुक्त किया जाता है और एसआरओ 1001 दिनांक 20 मई 1961 के माध्यम से 1950 अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियमित सेना में समकक्ष रैंक के साथ अधिसूचित किया जाता है।

30. वैधानिक ढांचे के मद्देनजर, यह प्रदर्शित होता है कि 1950 अधिनियम और सेना नियम, 1954 को केवल अनुशासन के उद्देश्य से जीआरईएफ के नागरिक कर्मियों पर लागू किया गया है। कारण स्पष्ट हैं. जीआरईएफ केंद्र सरकार के अधिकार के तहत गठित और बनाए रखा गया एक बल है, इसकी इकाइयां भारतीय सेना की तर्ज पर स्थापित की गई हैं, यह सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित सेना के साथ घनिष्ठ समन्वय के तहत काम करती है, भारतीय सेना को अपनी परिचालन भूमिका निभाने में सुविधा प्रदान करती है, आदि। इसलिए, यह उचित महसूस किया गया है कि 1950 अधिनियम को अनुशासन के हित में आवश्यक समझे जाने पर केंद्र सरकार द्वारा गठित और बनाए गए बल पर लागू किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जीआरईएफ कर्मियों को विधायी योजना के तहत दोहरे अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन किया जाता है, और ऐसी व्यवस्था स्वीकार्य है जैसा कि आर. विस्वान (उपरोक्त) में किया गया है। जब अपराध ऐसा हो कि 1950 अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि जीआरईएफ तक

बढ़ाया गया है, अनुशासन के उद्देश्य से लागू होते हैं, तो यह 1950 अधिनियम के तहत सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए खुला होगा, इसके प्रावधानों के तहत अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और यदि दोषी पाया गया, उचित दंड दिया जाएगा। इस सन्दर्भ में हम एक उदाहरण दे सकते हैं। यदि कोई अपराध किसी शत्रु, सक्रिय सेवा पर अपराध, विद्रोह, परित्याग, अवज्ञा आदि के संबंध में किया जाता है, तो अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए, कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमे के माध्यम से अपराधी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जा सकती है। अन्य अनुशासनात्मक मामलों में, सक्षम प्राधिकारी सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत आगे बढ़ने का निर्णय ले सकता है जिसमें अधिकतम स्वीकार्य सजा केवल 'सेवा से बर्खास्तगी' है।

31. इस पृष्ठभूमि में, अधिकरण का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाना है। जैसा कि देखा गया है, 2007 अधिनियम को 1950 अधिनियम, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन व्यक्तियों पर लागू किया गया है, इन अधिनियमों के अधीन सेवानिवृत्त कर्मियों, उनके आश्रितों, उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों सहित जहां तक उनके सेवा मामलों के लिए यह संबंधित है। धारा 4 और 5 के संदर्भ में गठित न्यायाधिकरण को दोहरे क्षेत्राधिकार के साथ निहित किया गया है, जैसे कि धारा 14 में प्रदान किए गए सेवा मामलों में क्षेत्राधिकार, शक्तियां और अधिकार और अधिनियम की धारा 15 के तहत कोर्ट मार्शल के खिलाफ अपील के मामले में क्षेत्राधिकार।

32. हालांकि, जीआरईएफ कर्मियों के लिए कोर्ट मार्शल के फैसलों से उत्पन्न अपीलों को सुनने के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के अधिकार क्षेत्र की स्थिति, हालांकि, एक अलग स्तर पर खड़ी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अध्याय V1 यानी अपराध, अध्याय VII यानी सजा, अध्याय X यानी 'कोर्ट मार्शल' आदि के प्रावधान पूरी ताकत से लागू होते हैं, यहां और वहां मामूली अपवादों और संशोधनों के अधीन, जैसा कि जीआरईएफ पर लागू होता है। इसलिए, जीआरईएफ कर्मियों के लिए कोर्ट मार्शल के

माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न सजाओं से संबंधित 1950 अधिनियम के प्रावधानों को एएफटी के समक्ष लागू किया जा सकता है और एएफटी के पास कोर्ट मार्शल के फैसलों से उत्पन्न होने वाली अपीलों को सुनने का अधिकार क्षेत्र होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त मामलों के संबंध में एएफटी का क्षेत्राधिकार होगा। उक्त न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र से वंचित करना अधिनियम 1950 और 2007 अधिनियम के तहत शामिल प्रावधान के विपरीत होगा। संक्षेप में, जीआरईएफ के कर्मियों द्वारा एएफटी से संपर्क करने का अधिकार, जिन पर उसी अधिनियम के तहत कोर्ट मार्शल का मुकदमा चलाया जाता है, को मान्यता दी जानी चाहिए। साथ ही, यदि सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत आयोजित विभागीय कार्यवाही के माध्यम से ग्रेप कर्मियों पर सजा दी जाती है, तो जाहिर तौर पर इसे एएफटी के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि ऐसे मामलों में जुर्माना एक के तहत नहीं होगा। 1950 अधिनियम लेकिन सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत होगा। वर्तमान में कानून मौजूद होने के कारण भेद करना होगा।

33. उपरोक्त से, जो कानूनी स्थिति उभरती है वह यह है कि एएफटी के पास जीआरईएफ कर्मियों के लिए कोर्ट मार्शल के फैसलों से उत्पन्न होने वाली अपीलों को सुनने का अधिकार क्षेत्र होगा (i) केवल इसी सीमा तक एएफटी का क्षेत्राधिकार होगा। साथ ही यदि सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत आयोजित विभागीय कार्यवाही के माध्यम से जीआरईएफ कर्मियों पर दंड लगाया जाता है तो उसे एएफटी के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है और (ii) एएफटी के पास शिकायतों को सुनने और निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। जीआरईएफ कर्मी अपनी सेवा के नियमों और शर्तों से संबंधित हैं या वैकल्पिक रूप से 'सेवा मामले' रखते हैं।

34. इस स्तर पर, यह दोहराना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के पक्ष में 5.11.2012 को अंतिम आदेश पारित किया था। जैसा भी हो, ट्रिब्यूनल के पास अपीलकर्ता

द्वारा उसके समक्ष उठाए गए अपग्रेडेशन या लिस की प्रकृति के मुद्दे से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। मुद्दे से निपटने के लिए अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की कमी के अभाव में, उक्त निर्णय निरर्थक है। कानून में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह अच्छी तरह से व्यवस्थित है। कानून में कहा गया है कि पारित निर्णय निरर्थक है यदि यह किसी ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जिसके पास कोई अंतर्निहित क्षेत्राधिकार नहीं है। डिक्री को शून्यता कहे जाने को इस अर्थ में समझा जाना चाहिए कि यह डिक्री पारित करने वाली अदालत की शक्तियों का अधिकारातीत अधिकार है, न कि केवल शून्यकरणीय डिक्री। [देखें हीरालाल मूलचंद दोशी बनाम बरोट रमन लाल रणछोड़दास']।

35. उपरोक्त के मद्देनजर, हम अपील को खारिज करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं कि उसके पास केवल अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद से निपटने का अधिकार क्षेत्र है। भारत संघ और उसके पदाधिकारियों द्वारा ट्रिब्यूनल द्वारा पारित दिनांक 18.6.2012 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को नकार दिया गया था। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा की गई शिकायत का वास्तव में किसी भी सक्षम मंच द्वारा समाधान नहीं किया गया है। उनकी शिकायत का निपटारा कानून के मुताबिक किया जाना चाहिए।' स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ता को तीन महीने के भीतर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देते हैं। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि यदि यह मामला दायर किया गया है, तो इसे अपने गुण-दोष के आधार पर निपटाया जाए, न कि इसे देरी और लापरवाही के आधार पर लटकाया जाए। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

निधि जैन अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।